CEASI TIMES

21st July 2025

HINDI

CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

CEDSI
CENTRE OF EXCELLENCE FOR DAIRY SKILLS IN INDIA

CEFMI
Centre of Excellence for Farm Mechanization Skills in India

CEHSI
Centre of Excellence for Horticulture Skills in India

www.ceasi.in

हमारे बारे में

हम कौन हैं:

"सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEASI)" एक स्वायत्त संस्था है, जो "एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (ASCI)" के अधीन कार्य कर रही है। यह संस्था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत किसानों, मजदूरी श्रमिकों, स्वरोजगार में लगे पेशेवरों, विस्तार कार्यकर्ताओं आदि के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण का कार्य करती है।

CEASI कृषि के विभिन्न उप-क्षेत्रों में स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों की शीर्ष संस्था है, जैसे कि:

- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेयरी स्किल्स इन इंडिया (CEDSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEHSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फार्म मेकनाइजेशन स्किल्स इन इंडिया (CEFMI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर (CoE-CRA)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर (CoE-AI)

हम क्या करते हैं:

- **कौशल विकास और क्षमता निर्माण:** कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में हितधारकों की आवश्यकताओं के आधार पर क्षमता निर्माण।
- **ज्ञान प्रबंधन:** वर्क्फोर्स मानकों को समर्थन देने हेतु QPs, NOS, स्किल गैप रिपोर्ट और न्यूज़लेटर्स का विकास।
- **अनुसंधान:** उद्योग की मांगों के अनुसार आवश्यकताओं की पहचान और कौशल अंतर को पाटने के लिए अनुसंधान।
- **नीति समर्थन और परामर्श सेवाएं:** नवाचार साझा करने और क्षेत्रीय चुनौतियों को हल करने हेतु नेटवर्क् का निर्माण।

हमारा विज़न

एक स्वायत्त उत्कृष्टता संस्थान जो कृषि में उच्च कौशलयुक्त कार्यबल विकसित करने के लिए समर्पित है, नवाचार, तकनीकी प्रगति और सतत प्रथाओं के माध्यम से भारतीय कृषि की समृद्धि और लचीलापन बढ़ाने के लिए कार्यरत है।

हमारा मिशन

राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उन्नत कृषि पद्धतियों में कौशल विकास के लिए अग्रणी संगठन के रूप में उभरना, जो सततता, लाभप्रदता, क्षमता निर्माण, ज्ञान प्रसार, नीति समर्थन और नवाचार आधारित अनुसंधान के माध्यम से कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करता है।

CEASI का प्रभाव:

CEASI भारतीय कृषि में एक परिवर्तनकारी बदलाव ला रहा है, जो व्यक्तियों को सशक्त बनाने, कौशल को निखारने और देशभर में समुदायों को उन्नत करने का कार्य कर रहा है।

- **15+ राज्य**
- **15 एफपीओ को प्रशिक्षित और सहयोग प्रदान किया गया**
- **20,000 कृषि / डेयरी पेशेवरों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया**
- **5000+ उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया**
- **3000+ महिलाओं को सशक्त बनाया गया**
- **30,000+ जीवन को प्रभावित किया गया**

हैदराबाद में नया अनुसंधान केंद्र टिकाऊ खेती को देगा बढ़ावा

अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT) और एक निजी कृषि यंत्र निर्माता कंपनी के सहयोग से हैदराबाद में एक नया अनुसंधान और विस्तार केंद्र शुरू किया जा रहा है। यह केंद्र टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने, फसल आधारित मशीनीकरण, मिट्टी की सेहत और जल उपयोग की दक्षता पर काम करेगा।

यह केंद्र विभिन्न फसलों और पारिस्थितिक क्षेत्रों में मशीन से कटाई जैसी तकनीकों की जांच करेगा और किसानों को कृषि यंत्रों के उपयोग और रखरखाव की ट्रेनिंग देगा। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों के लिए उपयुक्त मशीनीकरण मॉडल को बढ़ावा देना है।

यह केंद्र किसानों, वैज्ञानिकों, संस्थाओं और अन्य हितधारकों के लिए जानकारी साझा करने का मंच बनेगा। साथ ही, यह सामुदायिक उपयोग के डिजिटल यंत्र किराया मॉडल भी दिखाएगा जिससे किसान बिना यंत्र खरीदे उनका उपयोग कर सकें।

इस प्रयास का उद्देश्य रासायनिक उपयोग को कम करना, श्रमिकों पर निर्भरता घटाना और पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा देना है।

कृषि और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में AI के उपयोग के लिए Cropin और Wipro में साझेदारी

Agri-tech कंपनी Cropin और तकनीकी सेवा प्रदाता Wipro ने कृषि और खाद्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग को लेकर साझेदारी की है। इस सहयोग का मकसद कृषि आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता, निगरानी और टिकाऊपन को बेहतर बनाना है।

यह पहल डेटा की असंगठित स्थिति, मौसम की अनिश्चितता और पर्यावरणीय नियमों की बढ़ती मांग जैसी चुनौतियों से निपटने पर केंद्रित है। दोनों कंपनियाँ AI-आधारित समाधान तैयार करेंगी जो कृषि निर्णयों में मदद करेंगे।

यह साझेदारी ऐसे समय में हुई है जब जलवायु परिवर्तन, बाज़ार में उतार-चढ़ाव और नीतिगत बदलाव कृषि आपूर्ति पर असर डाल रहे हैं। यह सहयोग खेती में डिजिटल उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने की व्यापक कोशिशों का हिस्सा है।

कर्नाटक में ड्रोन तकनीक से खेती में उत्पादन बढ़ा, पानी की बचत

बेंगलुरु स्थित कृषि विश्वविद्यालय (UAS) के एक अध्ययन में पाया गया कि ड्रोन के उपयोग से उंगलियों की बाजरा (रागी) और तुअर दाल में उत्पादन बढ़ा है और कीटनाशकों के छिड़काव में पानी की खपत 90% तक घटी है। यह अध्ययन 2023 से 2025 के बीच कर्नाटक के 10 जिलों में किया गया।

शोधकर्ताओं ने ड्रोन उपयोग के लिए एक स्थानीय मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाई, जिसमें छिड़काव की ऊंचाई, समय और रसायनों की मात्रा शामिल थी। रागी में 5% और तुअर में 10% तक उत्पादन में बढ़ोतरी देखी गई, जबकि पानी की खपत 500 लीटर से घटकर 55 लीटर प्रति हेक्टेयर हो गई।

अध्ययन में श्रमिकों की कमी और रसायनों के स्वास्थ्य प्रभावों पर भी ध्यान दिया गया। यह निष्कर्ष दर्शाते हैं कि ड्रोन तकनीक छोटे किसानों के लिए उपयोगी हो सकती है।

कृषि मंत्री ने गुजरात में मूंगफली के खेतों का दौरा किया

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गुजरात के जूनागढ़ जिले के मानेकवाड़ा गांव में मूंगफली के खेतों का दौरा किया। उन्होंने खेत में किसानों से बातचीत की और खुद भी निराई और गुड़ाई जैसे कामों में हिस्सा लिया।

बातचीत में बीज की किस्मों, खादों, उत्पादन तकनीकों और सिंचाई की समस्याओं पर चर्चा हुई। किसानों ने फसल के मौसम, लागत और बाजार से जुड़ी चुनौतियाँ साझा कीं। मंत्री ने 'गिरनार-4' मूंगफली किस्म में विशेष रुचि दिखाई और अधिकारियों से जानकारी ली।

उन्होंने ड्रोन और अन्य कृषि उपकरणों को भी देखा और किसानों से उनके उपयोग पर फीडबैक लिया। यह दौरा किसानों की समस्याओं को समझने और नीतियों में सुधार के प्रयास का हिस्सा था।

पश्चिम बंगाल में फूड प्रोसेसिंग और बागवानी निवेश को नया बढ़ावा

पश्चिम बंगाल फूड प्रोसेसिंग और बागवानी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत पौध सामग्री, मॉडल नर्सरी, जैविक खेती और मजबूत फसलोत्तर प्रबंधन को बढ़ावा दे रहा है। राज्य में कोल्ड चेन अवसंरचना के विस्तार, संरक्षित खेती और मूल्य संवर्धन क्षमताओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आने वाले तीन वर्षों में मक्का की खेती का रकबा 60,000 हेक्टेयर तक बढ़ाने की योजना है, ताकि पशु, मुर्गी और मछली चारे की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। साथ ही, कृषि क्षेत्र में 70% महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए उनके सशक्तिकरण को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

हर साल लगभग 163 लाख टन सब्जियों और 40 लाख टन फलों के उत्पादन के साथ, पश्चिम बंगाल में लॉजिस्टिक्स, कोल्ड चेन और निर्यात में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। केला, अनानास, ब्लूबेरी और अदरक जैसी फसलों के लिए ऊतक संवर्धन (टिशू कल्चर) को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों, एफपीओ और उद्यमियों के साथ भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए, वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य में 24,000 से अधिक फूड प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित की गई हैं, जो इस क्षेत्र की प्रगति को दर्शाती हैं।

कश्मीर में बागवानी अधिकारियों और उद्यमियों के लिए कोल्ड चेन प्रशिक्षण कार्यशाला

डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर, कश्मीर में कोल्ड चेन घटकों के कार्यान्वयन हेतु नवीनतम इंजीनियरिंग दिशानिर्देशों और न्यूनतम प्रणाली मानकों पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसका उद्देश्य घाटी में फसलोत्तर अवसंरचना को सुदृढ़ करना था। इसमें बागवानी विभाग के अधिकारी, निजी उद्यमी और उद्योग से जुड़े हितधारक शामिल हुए। विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण के दौरान प्रायोगिक कार्यान्वयनें, परिचालन मानकों और कोल्ड चेन व्यवस्था में मौजूदा खामियों पर चर्चा की। यह कार्यशाला, एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के तहत, आधुनिक फसलोत्तर प्रबंधन और कोल्ड चेन संचालन की जानकारी प्रदान करने पर केंद्रित रही।

नियंत्रित वातावरण भंडारण संचालकों और वाणिज्य मंडल के प्रतिनिधियों ने वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर कोल्ड चेन घटकों के लिए इंजीनियरिंग मानकों पर आधारित दिशा-निर्देश पुस्तिका विभाग को औपचारिक रूप से भेंट की गई। किसानों और उद्यमियों को निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन का आश्वासन दिया गया। कार्यशाला में जिलेवार बागवानी अधिकारी, उद्योग संघ और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि सक्रिय रूप से शामिल रहे।

आंध्र प्रदेश ने 2047 के लिए आर्थिक विकास का खाका पेश किया

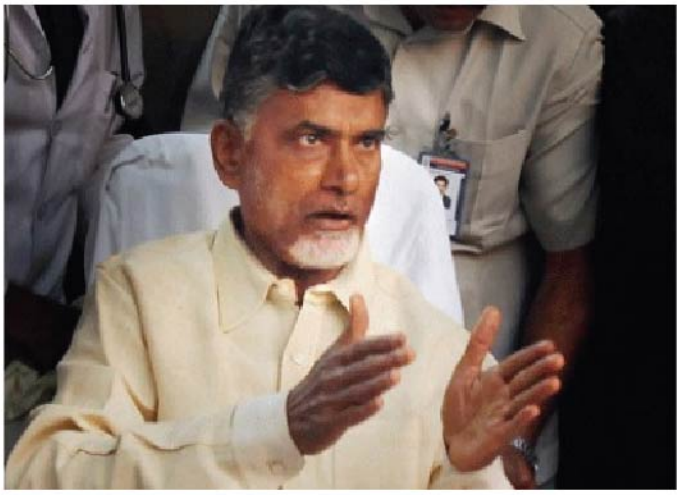

आंध्र प्रदेश ने 2047 तक भारत का अग्रणी राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए आर्थिक विकास की महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की है। इसके तहत राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 2.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और निर्यात 450 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह विजन औद्योगिक विकास, अधोसंरचना विस्तार और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। राज्य की ताकत — कुशल मानव संसाधन, उपजाऊ कृषि भूमि और रणनीतिक तटरेखा — को आधार बनाते हुए हर 50 किलोमीटर पर बंदरगाह विकसित करने, हवाई अड्डों के विस्तार और विश्वस्तरीय सड़क नेटवर्क तैयार करने की योजना है, जिससे आंध्र प्रदेश को भविष्य का लॉजिस्टिक्स हब बनाया जाएगा।

राज्य कौशल विकास और वैश्विक संस्थानों के सहयोग से मानव संसाधनों को उन्नत करने पर भी जोर दे रहा है। एक प्रमुख पहल के तहत, जनवरी 2026 से अग्रणी तकनीकी कंपनियों के सहयोग से क्वांटम कंप्यूटिंग शुरू की जाएगी। अमरावती में "क्वांटम वैली" विकसित करने की योजना है, जिससे राज्य नवाचार में अग्रणी भूमिका निभाएगा। निवेशकों को सक्रिय समर्थन देने का आश्वासन इस विजन का प्रमुख हिस्सा है।

आलू और केले की रिकॉर्ड पैदावार से भारत में बागवानी उत्पादन नई ऊंचाई पर

भारत का बागवानी उत्पादन 2024-25 फसल वर्ष में 367.72 मिलियन टन के नए शिखर पर पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष के 354.74 मिलियन टन की तुलना में 3.66% अधिक है। इस वृद्धि का प्रमुख कारण 60 मिलियन टन से अधिक की रिकॉर्ड आलू उत्पादन और प्याज उत्पादन में 6.5 मिलियन टन की उल्लेखनीय वृद्धि है। कुल उत्पादन में वृद्धि का मुख्य आधार क्षेत्र विस्तार नहीं बल्कि उत्पादन क्षमता में सुधार रहा है।

बागवानी फसलों के तहत कुल क्षेत्रफल में केवल 1.81 लाख हेक्टेयर की मामूली वृद्धि हुई, जिससे कुल क्षेत्रफल 292.67 लाख हेक्टेयर पहुंच गया। सीमित क्षेत्र विस्तार के बावजूद, उत्पादन में लगभग 13 मिलियन टन की वृद्धि हुई, जो बेहतर उत्पादकता और उन्नत कृषि प्रबंधन का परिणाम है। आलू और प्याज जैसे प्रमुख फसलों से प्रेरित यह निरंतर विकास, भारत की कृषि उत्पादन क्षमता और भविष्य की संभावनाओं को दर्शाता है। यह प्रवृत्ति देश की खाद्य सुरक्षा और कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है।

झारखंड के डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डोडला डेयरी ने ओसाम डेयरी का अधिग्रहण किया

डोडला डेयरी लिमिटेड ने रांची स्थित ओसाम डेयरी का ₹271 करोड़ में अधिग्रहण किया है, जो पूर्वी भारत में कंपनी के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिग्रहण के तहत ओसाम की 1,000 मिल्क कलेक्शन सेंटर, 19 मिल्क चिलिंग यूनिट्स और प्रतिदिन 1.1 लाख लीटर दूध की खरीद क्षमता शामिल है, जिससे 25,000 से अधिक डेयरी किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

यह कदम ओसाम की ग्रामीण बुनियादी संरचना को डोडला की राष्ट्रीय डेयरी नेटवर्क् से जोड़ता है, जिससे किसानों को बेहतर बाज़ार पहुंच, आधुनिक प्रोसेसिंग सुविधाएं और तेज़ भुगतान जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

तीन दशकों से अधिक के अनुभव वाली डोडला डेयरी वर्तमान में पांच राज्यों में दूध की खरीद करती है और 13 राज्यों में अपने उत्पाद वितरित करती है। ओसाम के जुड़ने से कंपनी की पूर्वी भारत में उपस्थिति और मजबूत होगी और दूध आपूर्ति श्रृंखला अधिक सुचारू बनेगी।

यह अधिग्रहण ग्रामीण आय में वृद्धि, दूध संग्रहण की दक्षता में सुधार और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने की संभावना को दर्शाता है। यह झारखंड के डेयरी क्षेत्र में एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर संकेत करता है, जहां बुनियादी ढांचे का तालमेल बढ़ती बाज़ार मांग के अनुरूप किया जा रहा है।

ओडिशा ने डेयरी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए एनडीडीबी से किया साझेदारी

ओडिशा सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के साथ साझेदारी की है ताकि राज्य के डेयरी क्षेत्र को मजबूती दी जा सके। इस पहल के तहत, ओएमएफईडी (OMFED) 4,000 उच्च-दुग्ध उत्पादन वाली गायें प्रदान करेगा और एक गोबर आधारित बायोगैस संयंत्र स्थापित करेगा, जिससे 15 लाख से अधिक डेयरी किसानों को लाभ मिलेगा।

'कामधेनु योजना' के अंतर्गत राज्य 10,000 गायों का वितरण और 70% किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य वर्तमान 72 लाख लीटर से दुग्ध उत्पादन को 2047 तक 274 लाख लीटर तक पहुंचाना है।

ओएमएफईडी के अरिलो संयंत्र में दूध टैंक, पैकेजिंग इकाइयों और स्टाफ क्वार्टर जैसी बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया जा रहा है। साथ ही, ओएमएफईडी के विविध डेयरी उत्पाद युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहे हैं।

एक हालिया समझौते के तहत जगन्नाथ मंदिर में महाप्रसाद की तैयारी के लिए 30 मीट्रिक टन घी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। यह सहयोग राज्य के डेयरी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकता, स्थिरता और ग्रामीण आजीविका में उल्लेखनीय सुधार लाने की उम्मीद है।

असम में दुग्ध क्षेत्र को सशक्त करने के लिए पुराबी डेयरी प्लांट का विस्तार

वेस्ट असम मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड (WAMUL) ने गुवाहाटी के पांजाबाड़ी स्थित पुराबी डेयरी प्लांट के विस्तार की पहल की है, जिससे इसकी दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन (LLPD) से बढ़कर 3 LLPD हो जाएगी। यह ₹104 करोड़ की परियोजना WAMUL और NDDB के बीच Advantage Assam 2.0 समिट में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आजीविका और डेयरी अवसंरचना को सशक्त बनाना है।

विस्तार के तहत पैकेज्ड दूध (2 LLPD), आइसक्रीम (20 TLPD, जिसे 30 TLPD तक बढ़ाया जा सकता है) और अन्य डेयरी उत्पादों (70 TLPD) के लिए नई उत्पादन इकाइयाँ शामिल हैं। यह पहल असम डेयरी विकास योजना (Assam Dairy Development Plan) के अंतर्गत आती है, जिसका लक्ष्य राज्य भर में 10 LLPD तक दुग्ध प्रसंस्करण करना है।

यह प्लांट पहले विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित APART परियोजना के तहत 60,000 लीटर प्रतिदिन से 1.5 LLPD तक उन्नत किया गया था और 18 महीनों में ही पूर्ण क्षमता पर पहुँच गया था, जिससे इसके और विस्तार की आवश्यकता पड़ी। उन्नत संयंत्र से दूध संग्रहण, प्रसंस्करण दक्षता और बाज़ार पहुंच में सुधार होने की उम्मीद है, जो असम की सहकारी डेयरी व्यवस्था को और मज़बूत करेगा और बढ़ती उपभोक्ता मांग को पूरा करेगा।

एनडीआरआई ने क्लोन की गई गिर गाय से आईवीएफ बछड़े का सफल उत्पादन किया

ICAR-राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (NDRI) ने गिर नस्ल की एक क्लोन की गई गाय से इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) के माध्यम से सफलतापूर्वक बछड़े का जन्म कराकर पशुपालन विज्ञान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह प्रक्रिया पारंपरिक प्रजनन चक्र की तुलना में लगभग 10 महीने कम समय में पूरी हुई है। साहीवाल नस्ल की एक सरोगेट गाय से जन्मा यह बछड़ा केवल 39 महीनों में "गंगा" नामक उत्कृष्ट क्लोन गिर गाय की दूसरी पीढ़ी को दर्शाता है, जबकि सामान्यतः यह चक्र 46–50 महीने में पूरा होता है।

गंगा, भारत की पहली क्लोन गिर गाय है, जिसे NDRI द्वारा हैंडमेड क्लोनिंग तकनीक से 16 मार्च 2023 को विकसित किया गया था। मात्र 18 महीनों में प्रजनन योग्यता प्राप्त करने के बाद, अल्ट्रासाउंड-निर्देशित, गैर-सर्जिकल ओवम पिक-अप (OPU) विधि से इसके अंडाणु एकत्र किए गए। इन्हें एक श्रेष्ठ गिर बैल के वीर्य से निषेचित कर भ्रूण को सरोगेट गाय में स्थापित किया गया।

यह उपलब्धि भारत में पहली बार क्लोनिंग और IVF तकनीकों के संयोजन से देशी नस्लों के तीव्र प्रसार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वैज्ञानिकों के अनुसार, इस नवाचार से उच्च गुणवत्ता वाले पशुओं का उत्पादन तेज़ी से संभव होगा, जिससे दुग्ध उत्पादकता में सुधार, देशी नस्लों का संरक्षण और कृत्रिम गर्भाधान (AI) कार्यक्रमों के लिए श्रेष्ठ सांडों का उत्पादन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

यह सफलता उन्नत प्रजनन जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत को दुग्ध क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है।

कृषक हित और बाजार पारदर्शिता के लिए बायोस्टीमुलेंट्स पर सख्त निगरानी

बायोस्टीमुलेंट्स — जो पौधों की वृद्धि और उत्पादकता बढ़ाने वाले पदार्थ हैं — को आधिकारिक रूप से उर्वरक या कीटनाशकों से अलग श्रेणी में रखा गया है। ये पदार्थ पौधों की जैविक प्रक्रियाओं को सक्रिय कर पोषक तत्व अवशोषण, उत्पादन और तनाव सहनशीलता में वृद्धि करते हैं। हालांकि इनकी मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन प्रभावशीलता और जबरन बिक्री की शिकायतों के चलते सरकार ने इनके नियमन को सख्त कर दिया है। वर्ष 2021 में उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO) में संशोधन कर बायोस्टीमुलेंट्स को विधिवत पंजीकरण और मान्यता के दायरे में लाया गया।

पहले बिना कड़ी निगरानी के बिक रहे ये उत्पाद अब परीक्षण और आधिकारिक स्वीकृति के बिना बाजार में नहीं बेचे जा सकते। अस्थायी पंजीकरण की सुविधा, जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया था, जून 2024 में समाप्त हो गई। अब बिना नियमित पंजीकरण के कंपनियां अपने स्टॉक की बिक्री नहीं कर सकतीं। यह कदम किसानों के हितों की सुरक्षा, जबरन बिक्री पर रोक और गुणवत्ता युक्त उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। तेजी से बढ़ते इस बाजार में पारदर्शिता और जिम्मेदार व्यापार की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है।

भारत और अर्जेंटीना के बीच कृषि सहयोग को मजबूती

भारत और अर्जेंटीना के बीच कृषि सहयोग पर दूसरी संयुक्त कार्य समूह (JWG) बैठक हुई। इसमें दोनों देशों ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के कृषि सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी और अर्जेंटीना के कृषि सचिव श्री सर्जियो इराएता ने की।

बैठक में कृषि मशीनीकरण, बीज तकनीक, कीट प्रबंधन, जलवायु-स्थिर खेती, और संयुक्त अनुसंधान जैसे विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही बागवानी, तिलहन व दालों की वैल्यू चेन, कार्बन क्रेडिट, जैव-कीटनाशक और टिड्डी नियंत्रण जैसे मुद्दे भी शामिल थे।

भारतीय प्रतिनिधियों ने डिजिटल कृषि, जोखिम प्रबंधन और किसानों के लिए वित्तीय सहायता जैसी नीतियों की जानकारी साझा की। यह सहयोग दोनों देशों के कृषि क्षेत्र में तकनीकी और ज्ञान आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा।

100 पिछड़े जिलों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए 'धन-धान्य कृषि योजना' को मंजूरी

सरकार ने वर्ष 2025-26 से शुरू होकर छह वर्षों की अवधि के लिए 'धन-धान्य कृषि योजना' को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य देश के 100 कम प्रदर्शन वाले जिलों में कृषि को सशक्त बनाना है। इन जिलों का चयन कम उत्पादकता, फसल विविधता की कमी और कृषि ऋण की सीमित पहुंच जैसे मानकों के आधार पर किया जाएगा।

यह योजना उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और सतत खेती को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत सिंचाई सुविधाओं, ब्लॉक व पंचायत स्तर पर भंडारण अवसंरचना और ऋण सुविधाओं में सुधार किया जाएगा।

योजना की विशेषता 11 मंत्रालयों की 36 चल रही योजनाओं का एकीकृत ढांचे में समावेश है, जिसे राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र की भागीदारी से लागू किया जाएगा। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तीन-स्तरीय निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। प्रत्येक जिले में प्रगतिशील किसानों की भागीदारी से स्थानीय योजना बनाई जाएगी। 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के माध्यम से प्रगति की मासिक निगरानी डिजिटल डैशबोर्ड पर की जाएगी।

गढ़चिरौली में काजू की खेती से किसानों को नई उम्मीद

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में किसान अब काजू की खेती कर अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोट्टा कोंडा गांव के किसान डोक्का मटामी ने अपने खेत में 200 काजू के पेड़ लगाए हैं और उम्मीद है कि दो साल में जब फसल तैयार होगी, तो उनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी।

अब तक यह इलाका धान की खेती के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले तीन सालों में राज्य कृषि विभाग और केरल के काजू एवं कोको बोर्ड के सहयोग से 608 हेक्टेयर में काजू के पौधे लगाए गए हैं।

कृषि अधिकारियों के अनुसार, गढ़चिरौली की गर्म और नम जलवायु काजू और अन्य उष्णकटिबंधीय फलों के लिए उपयुक्त है। अब बेहतर सड़कों और सुरक्षा के कारण दूर-दराज के गांवों तक पहुंचना आसान हुआ है।

सरकार आम, अमरूद, सीताफल और इमली की खेती भी बढ़ावा दे रही है। एटापल्ली के कासानसूर गांव में पौधशाला से किसानों को पौधे मिल रहे हैं। लक्ष्य है—गढ़चिरौली को पूर्वी महाराष्ट्र का फल उत्पादक क्षेत्र बनाना।

बाराबंकी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेयरी स्किल्स इन इंडिया द्वारा तीन दिवसीय डेयरी फार्मर उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेयरी स्किल्स इन इंडिया ने स्किल ग्रीन ग्लोबल के सहयोग से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में 15 से 17 जुलाई 2025 तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। यह पहल ग्रामीण युवाओं और किसानों को डेयरी फार्मर उद्यमिता मॉडल के तहत सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई थी।

इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को वैज्ञानिक डेयरी पालन के तरीकों से अवगत कराना, डेयरी कार्यों में मशीनीकरण को बढ़ावा देना और उन्हें स्थायी आजीविका के लिए उद्यमिता की क्षमताएँ विकसित करना था।

कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को पशुपालन, चारा उत्पादन, स्वच्छता, वित्तीय योजना और डेयरी में उपयोग होने वाले आधुनिक मशीनी उपकरणों के प्रयोग का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

यह कार्यक्रम पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीकों के संयोजन से डेयरी क्षेत्र की उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में ग्रामीण उद्यमिता तथा समावेशी विकास को गति देग

सीईएएसआई और एएससीआई के सहयोग से एग्रीकल्चर मशीनरी डिमोंस्ट्रेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयो

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया (सीईएएसआई) द्वारा एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई) के सहयोग से एग्रीकल्चर मशीनरी डिमोंस्ट्रेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों से 250 बेनिफिशियरीज को एडवांस्ड फार्म मशीनरी के ऑपरेशन, मेंटेनेंस और डिमोंस्ट्रेशन में हैंड्स□ऑन स्किल्स प्रदान करना है।

यह प्रोग्राम खासकर रूरल यूथ, फार्म सर्विस प्रोवाइडर्स और एग्री□एंटरप्रेन्योरस के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वे मॉडर्न, मेकैनिकाइज्ड और क्लाइमेट□स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकें। ट्रेनिंग में सीड ड्रिल, हार्वेस्टर, पावर वीडर और अन्य एडवांस्ड इक्विपमेंट्स का प्रैक्टिकल यूज सिखाया जाएगा, साथ ही सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, ट्रबलशूटिंग और बेसिक रिपेयर्स की जानकारियाँ भी दी जाएँगी।

यह इनिशिएटिव स्किल गैप को ब्रिज करता है, जिससे फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मैनुअल ड्रेजरी कम होगी और टेक्नोलॉजी□ड्रिवन सस्टेनेबल फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा।

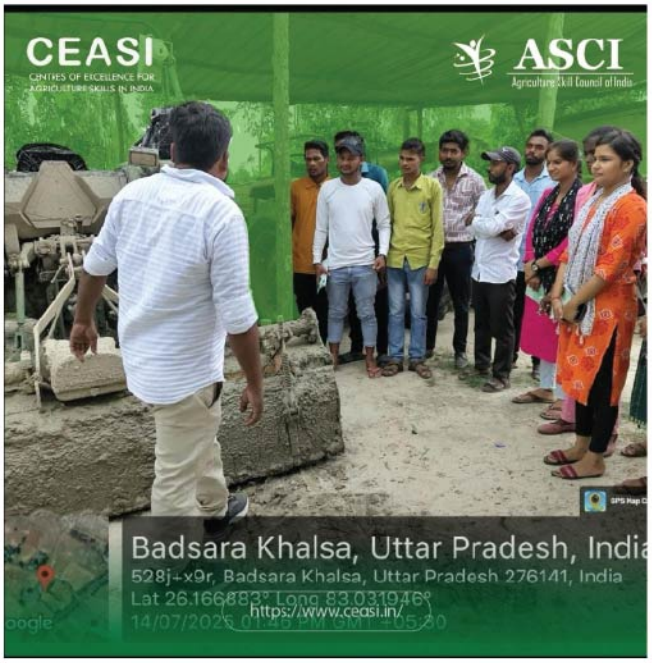

सेंटर ऑफ फार्म मेक्नाइजेशन स्किल्स इन इंडिया और एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड ने कुरुक्षेत्र में तीन दिवसीय कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) मेक्नाइजेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया

सेंटर ऑफ फार्म मेक्नाइजेशन स्किल्स इन इंडिया ने एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड के सहयोग से 21–23 जुलाई 2025 को कुरुक्षेत्र में कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए तीन दिवसीय रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित किया। यह वर्क्शॉप विशेष रूप से संगठन के बोर्ड मेंबर्स और सीईओ के लिए डिज़ाइन की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रासरूट पर मेक्नाइज्ड एग्रीकल्चर के लिए लीडरशिप और टेक्निकल स्किल्स को मजबूत करना था।

पहले दिन प्रतिभागियों ने एफपीओ गवर्नेंस मॉडल—बोर्ड रोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग—का अध्ययन कर एक स्ट्रांग इंस्टिट्यूशनल फाउंडेशन तैयार किया। दूसरे दिन उन्हें ट्रैक्टर, अटैचमेंट्स और अन्य एडवांस्ड फार्म मशीनरी के ऑपरेशन, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और रूटीन मेंटेनेंस का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया गया। तीसरे दिन एग्री बिज़नेस फाइनेंसिंग पर फोकस करते हुए क्रेडिट एप्रेज़ल मेथड्स, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशंस के साथ लिंकिंग स्ट्रेटेजीज़ सिखाई गईं।

स्पेशलिस्ट लीड क्लासरूम सेशंस, लाइव फील्ड डेमोंस्ट्रेशंस और पीयर नेटवर्किंग के संयोजन से यह इनिशिएटिव स्किल गैप को ब्रिज करते हुए फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी और क्लाइमेट स्मार्ट, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीबिज़नेस को बल देगी। सफल कम्पलीशन पर सभी पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएग

सश्वत मिठास पहल के तहत अयोध्या में टिकाऊ गन्ना खेती को सशक्त बनाना

सश्वत मिठास पहल के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया और यूपीएल एसएएस लिमिटेड के सहयोग से अयोध्या में टिकाऊ गन्ना खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

अब तक 415 किसानों का सर्वेक्षण करके उनकी मौजूदा खेती के तरीकों का आकलन किया गया और सुधार के क्षेत्र पहचाने गए। इन निष्कर्षों के आधार पर गांव□स्तर पर प्रदर्शन प्लॉट बनाए गए, जहाँ पानी की बचत, मिट्टी की सेहत सुधारने और जैविक इनपुट अप्लिकेशन जैसी तकनीकें दिखाई जा रही हैं।

समुदाय की भागीदारी और आपसी सीखने के लिए टीम ने 50 किसान मिटिंग्स और 4 फील्ड□डेज़ का आयोजन किया, जिनमें किसान एक्सपर्ट्स से चर्चा करते हैं, अनुभव साझा करते हैं और क्लाइमेट□रेसिलिएंट तकनीकों का लाइव अवलोकन करते हैं।

फील्ड रिसर्च, इंटरएक्टिव सेशंस और लाइव डेमोंस्ट्रेशंस के माध्यम से यह पहल किसानों को इको□फ्रेंडली और रिसोर्स□कनजर्विंग तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। इसका उद्देश्य सिर्फ गन्ने की पैदावार बढ़ाना नहीं, बल्कि अयोध्या क्षेत्र में दीर्घकालिक पारिस्थितिक संतुलन और टिकाऊ कृषि का स्थायी मॉडल विकसित करना है।

CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR
AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

(CEASI), Unit No. 101, First Floor, Greenwoods Plaza, Block 'B' Greenwoods City, Sector-45, Gurugram, Haryana-122009

+91 74287 06078

info@cedsi.in

www.ceasi.in

@ceasi_india